सरकार बनाएगी 30 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक

[पीटीआई | नई दिल्ली]

केंद्र सरकार गन्ना किसानों की बकाया रकम के भुगतान के लिए मिल मालिकों की मदद करने की योजना बना रही है। फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान ने गुरुवार को कहा कि मिल मालिकों की मदद करने के लिए चीनी का बफर स्टॉक 30 लाख टन किया जाएगा। इससे गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ रुपये बकाया भुगतान में मदद मिलेगी। चीनी की कीमत में तेज गिरावट के चलते शुगर मिलों की वित्तीय स्थिति काफी खराब है। अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018 के सीजन में रिकॉर्ड 3.16 करोड़ टन का प्रॉडक्शन हुआ है।

पासवान ने बताया, 'हम 30 लाख टन बफर स्टॉक रखने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए हम डिपार्टमेंट की राय ले रहे हैं।' राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मार्केट में चीनी की बड़ी मात्रा में उपलब्धता को लेकर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की थी। सूत्रों ने बताया कि फूड मिनिस्ट्री ने 30 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने का प्रपोजल दिया है। इसके साथ ही चीनी का मिनिमम एक्स-मिल प्राइस 30 रुपये किलो के आसपास तय करने, प्रत्येक मिल के लिए कोटा निर्धारित कर मिलों की स्टॉक सीमा बनाने और मिलों के लिए खुले बाजार में चीनी बेचने का मासिक चीनी कोटा जारी करने की व्यवस्था फिर से शुरू करने जैसे उपायों का सुझाव दिया गया है।

बफर स्टॉक 30 लाख टन होने से गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ रुपये बकाया भुगतान में मदद मिलेगी

मिलों के 20 लाख टन चीनी का भी एक्सपोर्ट न कर पाने की स्थिति में होने के कारण मिनिस्ट्री विकल्प पर विचार कर रही है। चीनी का एक्स-मिल प्राइस अभी 25.60 से 26.22 रुपये प्रति किलो ग्राम के दायरे में है। यह दाम उनकी लागत से कम बताया जा रहा है। सरकार ने इससे पहले गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में मदद के लिए मिलों को 5.50 रुपये प्रति क्विंटल की उत्पादन सब्सिडी देने को मंजूरी दी थी।

केंद्र ने पहले ही चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी दोगुनी कर 100 पर्सेंट कर दी है और डोमेस्टिक मार्केट में गिरते दाम को रोकने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है। मिलों को 20 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट करने के लिए कहा गया है। चीनी उत्पादन में दुनिया में भारत दूसरे स्थान पर है। 2016-17 में 203 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है।

The economic Times.
01-06-18.